

४५

प्रेषक,

डी० पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, जिला-नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: २७ जुलाई, 2011

विषय— अतिथि वार्ताओं के मानदेय की दरों का पुनरीक्षण।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं० दिनांक 537 / 02-VIII/2010 दिनांक 03.05. 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस राष्ट्रन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं० 24/८/76 का—प्र.स.को./1999 दिनांक 11 अगस्त 1999 के द्वारा अतिथि वार्ताकारों को अनुमन्य मानदेय की दरों को उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली की मा० शासी परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुक्रम में अकादमी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साधारण दर से रु० 600/- (रु० ६०: सौ मात्र) तथा विशिष्ट दर से रु० 1000/- (रु० एक हजार मात्र) निम्न शर्तों के अधीन निर्धारित किये जाने की, राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)— नियमित रूप से आमंत्रित किये जाने वाले स्थानीय वार्ताकारों को साधारण दर से मानदेय का भुगतान किया जाय।

(2)— बाहर से बुलाये जाने वाले विशेषज्ञ वार्ताकारों को विशिष्ट दर से मानदेय का भुगतान किया जाय।

2— जो अतिथि वार्ताकार शासकीय सेवा में हो, उन्हें उनकी अनुमन्यतानुसार धात्रा किराया तथा जो अतिथि वार्ताकार शासकीय सेवा में नहीं है उन्हें रेल की वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का काठगोदाम तक आने जाने का किराया एवं टैक्सी का किराया नियमानुसार अनुमन्य होगा।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित विभागों के आय व्यय की गदों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाले जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं० 74NP/XXVII(5)/2011-12 दिनांक: 21 जुलाई 2011 को प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहे हैं।

भवदीय

(डी० पी० गैरोला)
प्रमुख सचिव